

एयर इंडिया : वनिविश का मार्ग

संदर्भ

आश्चर्यजनक रूप से एयर इंडिया का रणनीतिक वनिविश नविशकों को लुभाने में असफल रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि कंपनी को एक आकर्षक नविश अवसर के रूप में देखा जाय, पूरी बिक्री प्रक्रिया और शर्तों पर फरि से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिये कंपनी को छोटी इकाइयों में पुनर्गठित किया जाना चाहिये। साथ ही इन इकाइयों का पुनर्गठन और नरिमाण कर बिक्री के दौरान अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना होगा।

एयर इंडिया को सात इकाइयों में पुनर्गठित करने की आवश्यकता

कंपनी को सात इकाइयों में पुनर्गठित किया जाना चाहिये-

1. वमिनन- यात्री और कार्गो (एयर इंडिया एक्सप्रेस और एलायंस एयर शामिल हैं)
2. लीजिंग - सभी स्वामित्व वाली वायुयान संपत्तियाँ
3. हवाईअड्डा सेवाएँ-ग्राउंड हैंडलिंग (पहले से नरिमति)
4. होटल (पहले से नरिमति)
5. रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ, पहले से ही बनाया गया)
6. लॉयल्टी कार्यक्रम-उड़ान वापसी
7. वरिसत (legacy) - अतिरिक्त संपत्तियाँ, मानव संसाधनों और देनदारियों को शामिल करना, यह अन्य कंपनियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं है।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव

- इन इकाइयों का पुनर्गठन और नरिमाण, बिक्री के दौरान अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करेगा और सरकार का वित्तीय नुकसान कम होगा।
- इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कंपनियों के बीच प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्रतस्पर्द्धी और बाज़ार दरों के अनुरूप हों।
- वमिनन इकाई के पुनर्गठन में टिकट मूल्य नरिधारण और लोड कारकों को अनुकूलित करने के लिये यातायात और मार्गों पर वसितृत अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिये।
- 11 वमिनन उप-प्रकारों के मशिरति वमिननों में तीन से कम नहीं होने चाहिये।
- भारत की अग्रणी एयरलाइन, इंडिगो में केवल एक वमिनन प्रकार अनुदेशति है, जिससे लागत और जटलिता कम आती है।
- पूरे वमिनन पोर्टफोलियो, एमआरओ सेवाओं, हवाईअड्डा सेवाओं और लॉयल्टी कार्यक्रम को पट्टे पर देने के लिये अन्य संस्थाओं के साथ प्रतस्पर्द्धी सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
- पुनर्गठन का मानव संसाधन हसिसा राजनीतिक रूप से मुश्कलि होगा लेकिन वित्तीय रूप से आवश्यक होगा।
- सभी महत्वपूर्ण कर्मचारियों को "बाज़ार स्तर पर" वमिनन इकाई में पुनर्स्थापति किया जाना चाहिये, यह किसी भी नविशक के लिये महत्वपूर्ण है।
- प्रासंगिक वमिनन अनुभव के साथ एक गतिशील और कुशल प्रबंधन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तरह नौकरशाही से प्रभावति न हो, आवश्यक होगा।
- सभी अतिरिक्त संपत्तियाँ (मुंबई कार्यालय, दलिली भूमिसंपत्ति आदी) और अतिरिक्त कर्मचारियों को वरिसत इकाई में स्थानांतरति किया जाना चाहिये।
- लगभग ₹ 50,000 करोड़ की सभी देनदारियों को भी वरिसत इकाई में स्थानांतरति किया जाना चाहिये, कंपनी को ऋण मुक्त बेचना महत्वपूर्ण है।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि खरीदार को अपनी पूंजी संरचना आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी को खरीदने की स्वतंत्रता है, इस प्रकार व्यापक बोली-प्रक्रिया में भागीदारों की अनुमति मिलति है।
- पुनर्गठित वमिनन इकाई, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए राजस्व (एक रूढ़िवादी अनुमान) के साथ एबिटदर (Abitdar) (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और करिए से अर्जति) 5,500 करोड़ रुपए होना चाहिये।
- वरिसत ऋण बोझ को कम करने के साथ बिक्री में वित्तीय नुकसान को तुरंत रोक दिया जाएगा।
- वमिनन इकाई की बिक्री के बाद लीजिंग इकाई, हवाईअड्डा सेवाओं की इकाई और होटल इकाई का मुद्रीकरण किया जाना चाहिये।
- लीजिंग इकाई का इक्वटी वैल्यू स्वामित्व वाले वमिनन के मूल्य में नहिति होता है। वर्तमान में लाभप्रद एयरपोर्ट सेवा इकाई तीसरे पक्षों से अपने राजस्व का 50% कमाति है, जिससे इसे रणनीतिक खलिाइयों के लिये वांछति अधगिरहण मलि जाता है।

एमआरओ इकाई और लॉयल्टी कार्यक्रम इकाई की भूमिका

- लॉयल्टी कार्यक्रम व्यापारियों द्वारा डज़ाइन की गई मार्केटिंग रणनीतियों की संरचना करने के लिये ग्राहकों को प्रोत्साहति करते हैं ताकि वे

प्रत्येक लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़े व्यवसायों की सेवाओं पर खरीदारी कर सकें।

- एमआरओ (maintenance, repair and overhaul-MRO) इकाई और लॉयल्टी कार्यक्रम इकाई में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त मूल्य होता है जिसे वमिनन इकाई और अन्य तृतीय पक्ष ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पुनर्गठन और वसितार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है।
- नागपुर में बोइंग द्वारा नरिमति एक नई सुविधा के नरिमाण के दावे के साथ भारत में एमआरओ सुविधाएँ सर्वश्रेष्ठ हैं।
- भारतीय एमआरओ सेवा प्रदाताओं को बकिरी से पहले इक्विटी हसिसेदारी के लिये साझेदारी करने में रुचि हो सकती है, जो वतितीय सुधार में मदद कर सकता है।
- वैकल्पिक रूप से बोइंग और एयरबस कषेत्रीय एमआरओ केंद्र बनाने में रुचि रख सकते हैं।
- लॉयल्टी कार्यक्रम के ग्राहक और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्त्ता आधार में वृद्धि की जानी चाहिये और लॉयल्टी बदि ऋणमुक्ति (redemption) (उदाहरण के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स) के अधिक मार्गों की अनुमति भी दी जानी चाहिये।
- इससे वमिनन इकाई के आकर्षक मार्ग नेटवर्क और टिकटों के लिये लॉयल्टी अंक का उपयोग कर आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- एमआरओ और लॉयल्टी कार्यक्रम इकाइयों को इक्विटी मूल्य अधिकतम करने तथा सरकार को लौटाने के लिये अपने ग्राहक आधार बनाने के बाद, तीन से पाँच वर्षों में बेचा जा सकता है।
- 50,000 करोड़ रुपए के मौजूदा वरिसत ऋण को अन्य कंपनियों की बकिरी से ₹ 15,000 करोड़ (लगभग 70% कमी) घटाया जा सकता है।
- सरकार के साथ शेष भूमि, कार्यालयों और दुनिया भर की अन्य संपत्तियों की बकिरी से ऋण को और कम किया जा सकता है।
- इस इकाई में सभी मानव संसाधन संपत्तियों को अन्य सरकारी उद्यमों में व्यवहार्य माना जाना चाहिये।

नषिकर्ष

- उपरोक्त सुझावों से एयर इंडिया को संभावति बोलीदाताओं के लिये एक आकर्षक नविश मलिया। इस प्रकार अतरिकित कर्मचारियों की बाधाओं, उपरोक्त बाजार अनुबंध और अन्य वरिसत लागतों को पुनर्नरिमति किया जा सकता है।
- उत्तरी अमेरिकी लीगेसी कैरियर तथा एशियाई, यूरोपीय और मध्य-पूर्वी फ्लैग कैरियर के पुनर्गठन में समान दृष्टिकोण लागू किया गया है।
- हालाँकि उपरोक्त सुझावों को नषिपादति करना आसान नहीं है लेकिन इसे आसान किया गया है और यहाँ भी इसे आसान किया जा सकता है।
- नागपुर में बोइंग द्वारा नरिमति नई एमआरओ सुविधाएँ भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/air-india-a-road-to-disinvestment>

